



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 30 अगस्त, 2006/8 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 27 अगस्त, 2007

संख्या वि0स0-लैज-गवरनमेंट बिल0/1-35/2007.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) वधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2007 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे0 आर0 गाज़टा,
सचिव ।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) विधेयक, 2007

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर यानों के उपयोग (चलाए जाने) पर निर्बन्धन ।
4. पास जारी करना ।
5. कतिपय मामलों में छूट ।
6. सील्ड सड़कों के लिए पास प्रदान करने और नवीकरण करने हेतु आवेदन तथा प्रक्रिया ।
7. प्रतिबन्धित सड़कों के लिए पास प्रदान करने और नवीकरण करने हेतु आवेदन तथा प्रक्रिया ।
8. कतिपय परिस्थितियों में अस्थायी पास प्रदान करना ।
9. पर्यटक पास प्रदान करना ।
10. साधारण शर्तें ।
11. इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन ।
12. शास्तियाँ ।
13. मामलों का संक्षिप्त निपटारा ।
14. पासों का रद्दकरण ।
15. अपील ।
16. फीस और जुर्मानों के आगमों का उपयोग ।
17. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति ।
18. शिथिल करने की शक्ति ।
19. अधिकारिता का वर्जन ।
20. कठिनाइयों का दूर किया जाना ।
21. नियम बनाने की शक्ति ।
22. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं ।
23. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
24. निरसन और व्यावृत्तियां ।

अनुसूचियाँ ।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) विधेयक, 2007

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

शिमला माल रोड की पहचान (महत्त्व), आम रास्ते के रूप में इसके उपयोग को रोकते हुए, पुनः लौटाने, शिमला नगर की सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर, लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में, पैदल चलने वालों को क्षोभ और क्षति से निवारित करने हेतु, यानीय यातायात को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 है ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ ।

(2) इस का विस्तार शिमला नगर की नगरपालिक सीमाओं तक है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "सहायक आयुक्त " से हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 9 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहायक आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) "कोर (मध्य) माल रोड" से शिमला क्लब से केन्द्रीय तारघर कार्यालय तक माल रोड का भाग अभिप्रेत है;

(ग) "उपायुक्त " से जिला के सामान्य प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है ;

- (घ) "मण्डलायुक्त " से राजस्व मण्डल शिमला का मण्डलायुक्त अभिप्रेत है ;
- (ङ) "भूतपूर्व उच्च पदस्थ" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी समय राज्य सरकार के किसी उच्च पदस्थ का पद धारण किया हो ;
- (च) "भूतपूर्व शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी समय शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति का पद धारण किया हो ;
- (छ) "निधि" से इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन स्थापित शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों की सुख-सुविधा निधि अभिप्रेत है ;
- (ज) "विभागाध्यक्ष " से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 (डेलीगेशन ऑफ फाईनैन्शल पावरज् रूलज, 1978) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति है, जिसे राज्य सरकार , आदेश द्वारा, विभागाध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे ;
- (झ) "कार्यालयाध्यक्ष (हैड ऑफ आफिस)" से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 (डेलीगेशन ऑफ फाईनैन्शल पावरज् रूलज, 1978) के नियम 14 के अधीन इस रूप में घोषित राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति है, जिसे सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा कार्यालयाध्यक्ष (हैड ऑफ आफिस) विनिर्दिष्ट करे ;
- (ञ). " उच्च पदस्थ " से निम्नलिखित अभिप्रेत है ,—
- (i) हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल ;
 - (ii) हिमाचल प्रदेश का मुख्यमन्त्री;
 - (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा का अध्यक्ष ;
 - (iv) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ;

- (v) हिमाचल प्रदेश के मन्त्री ;
 - (vi) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; और
 - (vii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा का उपाध्यक्ष;
- (ट) “माल रोड ” से छोटा शिमला चौक से बालूगंज, वाया ओक ओवर, शिमला क्लब, मैट्रोपोल होटल, कोर (मध्य) माल रोड, केन्द्रीय तारघर कार्यालय, गॉरटन कैसल और भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्थान, तक की सड़क अभिप्रेत है ;
- (ठ) “शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति ”से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—
- (i) हिमाचल प्रदेश से संसद सदस्य और हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य ;
 - (ii) राज्य सरकार का मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव ;
 - (iii) हिमाचल प्रदेश का महाधिवक्ता ;
 - (iv) थलसेना प्रशिक्षण कमाँड शिमला का जरनल ऑफिसर कमाँडिंग —इन —चीफ ;
 - (v) सुपर टाईम वेतनमान या इससे अधिक वेतनमान में, शिमला में तैनात, केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी और राज्य न्यायपालिका के अधिकारी ;
 - (vi) मेजर —जरनल या इससे ऊपर की पंक्ति के शिमला में तैनात सैन्य अधिकारी ;
 - (vii) नगर निगम शिमला का महापौर, उप—महापौर और पार्षद ; और
 - (viii) सुपरटाईम वेतनमान और इससे अधिक के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश के बोर्डों, निगमों या कानूनी (वैधानिक) आयोगों के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य ।
- (ड) “पास” से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क या दोनों पर वाहन चलाने के लिए जारी किया गया पास अभिप्रेत है ;
- (ढ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ण) “लोकोपयोगी यान” से आवश्यक सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाए जाने वाले निम्नलिखित वाहन अभिप्रेत हैं:—

- (i) आग बुझाने वाले यान ;
- (ii) रोगी वाहन और मृतक वाहन (डैड बॉडी वैन) ;
- (iii) डाक वाहन ;
- (iv) संचार एवं अन्य सेवाओं के रख-रखाव के लिए अभिनियोजित यान या गृह विभाग द्वारा अनुमोदित लोक परिवहन यान ;
- (v) गृह विभाग द्वारा अनुमोदित सरकारी (शासकीय) यानों सहित नगर निगम शिमला द्वारा स्वच्छता, जल आपूर्ति और अन्य नागरिक सेवाओं के रख-रखाव के लिए अभिनियोजित तथा नगर निगम अधिकारियों द्वारा दिन प्रतिदिन के निरीक्षण और उक्त कर्तव्यों के निष्पादन में उपयोग किए जाने वाले यान;
- (vi) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग , हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (बोर्ड), सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग तथा नगर निगम शिमला आदि से सम्बन्धित भारी वाहन जो किसी निर्माण या अनुरक्षण क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए अभिनियोजित किए गए हों ;
- (vii) जिला प्रशासन, शिमला तथा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा उच्च पदस्थों के साथ प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए अपेक्षित सरकारी यान; और
- (viii) राज्य सरकार द्वारा उच्च पदस्थों के संरक्षण के लिए सुरक्षा कर्मियों को ले जाने और उच्च पदस्थों के साथ चलने के लिए उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यान ।

(त) “प्रतिबन्धित सड़क” से अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट सड़क अभिप्रेत है;

- (थ) “अनुसूची” से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (द) “सील्ड सड़क” से अनुसूची -1 में निविर्दिष्ट सड़क अभिप्रेत है;
- (ध) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (न) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

- (प) “सुपर टाईम वेतनमान” से 18400—22400 रुपए का वेतनमान अभिप्रेत है;
- (फ) “अस्थायी पास” से इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी पास अभिप्रेत है ; और
- (ब) “पर्यटक पास” से इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन जारी पास अभिप्रेत है।

(2) उन समस्त शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. (1) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सभी सील्ड सड़कें, निम्नलिखित यानों के सिवाय समस्त मोटर यातायात के लिए बन्द होंगी, अर्थातः—

- (i) प्रत्येक उच्च पदस्थ का एक शासकीय यान और उसके साथ चलने वाले सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यान;
- (ii) राज्य के प्रत्येक भूतपूर्व मुख्यमन्त्री का एक यान;
- (iii) लोकोपयोगी यान जो राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा लोकहित में आवश्यक समझे जाएं;
- (iv) सील्ड सड़क पर चलाने हेतु शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति का एक शासकीय यान या भूतपूर्व उच्च पदस्थ का एक यान परन्तु छोटा शिमला से उच्च न्यायालय वाया ओक ओवर भाग का परमिट केवल तभी दिया जा सकेगा यदि उसका आवास या कार्य स्थान ऐसी सड़क पर है और ऐसा आवास या कार्य स्थान किसी प्रतिबन्धित सड़क या अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है;
- (v) आवासीय सम्पत्ति के सम्पत्ति करदाता या उच्च पदस्थ या शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसका निवास सील्ड सड़क पर है, को उसके स्वामित्वाधीन एक यान के लिए यदि उसका निवास किसी प्रतिबन्धित या अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है और उसके ऐसे आवासीय सम्पत्ति में गराज/पार्किंग सुविधा है; और
- (vi) इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी विधिमान्य अस्थायी पास धारक यान :

सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर यानों के उपयोग (चलाए जाने) पर निर्बन्धन।

परन्तु लोकोपयोगी यानों से भिन्न तथा भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके साथ चलने वाले सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यानों के सिवाए कोर (मध्य) माल रोड पर किसी भी यान को चलाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सचिव (गृह) समय-समय पर लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में, किसी सील्ड सड़क को यातायात के क्रॉस संचलन (क्रॉस मूवमेंट) में बाधा न होने देने के लिए यान की अधिकतम चौड़ाई (व्हील बेस) पर प्रतिबन्ध अधिरोपित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.— इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निवास-स्थान, यथास्थिति, प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क द्वारा सुगम्य समझा जाएगा यदि यह ऐसी सड़क से सौ मीटर की पथ-दूरी के भीतर स्थित है।

(2) अनुसूची -2 में विनिर्दिष्ट समस्त प्रतिबन्धित सड़कें सिवाए निम्नलिखित के सभी प्रकार के यानीय यातायात के लिए बन्द होंगी, अर्थात् :—

- (i) प्रत्येक उच्च पदस्थ के एक शासकीय यान और उनके साथ चलने वाले सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यान;
- (ii) राज्य के प्रत्येक भूतपूर्व मुख्यमंत्री का एक यान;
- (iii) लोकोपयोगी यान, जैसा राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा लोक हित में आवश्यक समझे जाएं;
- (iv) शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रयोग के लिए उद्दिष्ट (ईअरमार्क) एक सरकारी यान ऐसी तीन सड़कों के लिए जिन पर उसका चलाना लोक हित में है;
- (v) उच्च पदस्थ या शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति या भूतपूर्व उच्च पदस्थ या भूतपूर्व शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति या राज्य सरकार की प्रत्यायन समिति द्वारा प्रत्यायित राज्य स्तरीय प्रेस संवाददाता के स्वामित्व वाला एक यान ऐसी तीन सड़कों से अधिक के लिए नहीं;
- (vi) अभिहित पार्किंग स्थलों या समादत्त पार्किंग लॉटों (पेड पार्किंग लॉट्स) से मेहमानों को लाने ले जाने के लिए उस होटल या अन्य बोर्डिंग स्थान की बाबत, जो किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है, दो यानों तक; परन्तु यान होटल/ बोर्डिंग स्थान के स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा कम से कम तीन मास की अवधि के लिए पट्टे पर लिए गए हों;

- (vii) ऐसी प्रतिबन्धित सड़क पर स्थित सम्पत्ति में साधारणतया निवास करने वाले, जहां सम्पत्ति किसी अप्रतिबन्धित सड़क से सुगम्य नहीं है, गृहस्वामी या अधिभोगी की बाबत एक यान;
- (viii) सील्ड या प्रतिबन्धित सड़कों पर अवस्थित केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों से सम्बद्ध सरकारी यान उन्हें किसी सुविधाजनक प्रतिबन्धित सड़क के माध्यम से कार्यालय तक युक्तियुक्त परिवहन पहुंच दिलाने के लिए, यदि कार्यालय किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है;
- (ix) अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी विधिमान्य अस्थायी पास धारक यान; और
- (x) अधिनियम की धारा 9 के अधीन जारी विधिमान्य पर्यटक पास धारक यान ।

स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई स्थान किसी अन्य सड़क से सुगम्य समझा जाएगा यदि वह ऐसी सड़क से सौ मीटर की पथ दूरी के भीतर स्थित है।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार का सचिव (गृह) यातायात के आवागमन (क्वाण्टम) और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट प्रतिबन्धित सड़क पर चलाने के लिए यानों की अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा ताकि पैदल चलने वालों को खतरा, असुविधा या क्षोभ कारित न हो ।

4. (1) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम में उपबन्धित रीति में, धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों और इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों के अधीन पास जारी किए जाने पर यानों को अनुसूची 1 या 2 में विनिर्दिष्ट सड़कों पर चलाए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

पास जारी करना।

परन्तु किसी भी यान को तब तक पास प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' की बाबत विधिमान्य प्रमाण पत्र न हो।

(2) पास, लोक हित में निवास या सरकारी (शासकीय) कार्य-स्थान को पहुँच प्रदान करने के लिए दिया जाएगा और सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क के उस

भाग के लिए ही होगा जो निकटतम अन्य सड़क पर पहुँच के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है।

(3) जहां प्रतिबन्धित सड़क के लिए पासों की अधिकतम संख्या नियत की गई है वहां निम्नलिखित को अधिमान दिया जाएगा,—

(क) वरिष्ठ नागरिक और स्थायी रूप से निःशक्त (विकलांग); और

(ख) जिनका गराज/पार्किंग स्थान/ड्राइववेज या अन्य नियमित पार्किंग प्रबन्ध है।

(4) सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर निवास स्थान होने के कारण प्रति परिवार या निवास को एक से अधिक पास नहीं दिया जाएगा और केवल यह तथ्य कि निवास या सरकारी (शासकीय) कार्य-स्थान सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर है, पास प्रदान करने का हकदार नहीं बनाएगा।

कतिपय मामलों में छूट।

5. प्रतिबन्धित सड़क पर रात ग्यारह बजे से सुबह सात बजे के बीच मोटर यान चलाने के लिए कोई पास अपेक्षित नहीं होगा :

परन्तु यह कि सरकार, यानों और पैदल चलने वालों को क्षोभ या खतरे से निवारित करने के लिए किसी सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क की बाबत ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन (जिनके अन्तर्गत दिन में विनिर्दिष्ट समय के लिए सड़कों को इकतरफा या नो ट्रैफिक रोड घोषित करना है) जैसे विशिष्ट सील्ड/ प्रतिबन्धित सड़क की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, अधिरोपित कर सकेंगी।

सील्ड सड़कों के लिए पास प्रदान करने और नवीकरण करने हेतु आवेदन तथा प्रक्रिया।

6. (1) सील्ड सड़क पर यान चलाने के लिए पास को प्रदान करने हेतु आवेदन, ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, और राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा।

(2) सील्ड सड़क पर यान चलाने हेतु पास के मामले की प्रक्रिया के लिए सरकारी यान की दशा में सौ रुपए और प्राइवेट यान के लिए में पांच सौ रुपए की अप्रतिदेय फीस प्रभारित की जाएगी।

(3) सरकारी यान के लिए पास प्रदान करने हेतु एक हजार रुपए फीस और प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु दो हजार पांच सौ रुपए फीस प्रतिवर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगी:

परन्तु लोकोपयोगी यानों की बाबत कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी ।

(4) सील्ड सड़क पर यान चलाने के लिए पास का, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर, गृह विभाग द्वारा प्रतिवर्ष नवीकरण किया जा सकेगा और यदि आवेदक इसकी विधिमान्य अवधि के अवसान से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है तो पास व्यपगत समझा जाएगा:

परन्तु यदि आवेदक साबित कर देता है कि उसके पास नवीकरण के लिए समय पर आवेदन न करने के पर्याप्त कारण थे तो पास उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर, दो सौ रुपए प्रतिमास विलम्ब फीस या उसके भाग सहित, नवीकृत किया जा सकेगा ।

(5) सरकारी यान के लिए पास प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात्:—

- (क) यथास्थिति, राज्य सरकार के सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) या कार्यालयाध्यक्ष से इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र कि यान को, यथास्थिति, उच्च पदस्थ या सम्बद्ध शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ अभिनियोजित किया गया है; या यह एक लोकोपयोगी यान है;
- (ख) आवेदक द्वारा इस प्रभाव का स्वतः प्रमाणन (जहां लागू हो) कि उसका कार्यालय / निवास सील्ड सड़क पर है और वह किसी प्रतिबन्धित या किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है ;
- (ग) नए आवेदन की दशा में प्रक्रिया फीस के संदाय का सबूत और पास के नवीकरण की दशा में पूर्व पास की एक फोटो प्रति ;
- (घ) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' की बाबत विधिमान्य प्रमाण पत्र की प्रति ; और
- (ङ) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परन्तु उच्च पदस्थों और उन्हें सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यानों की बाबत आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामलों में रजिस्ट्रार जनरल या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आवेदन करेगा ।

(6) प्राइवेट यान के लिए पास को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात्:—

- (क) सबूत के तौर पर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति कि आवेदक यान का स्वामी है;
- (ख) सील्ड सड़क पर आवेदक के आवास की बाबत स्वतः प्रमाणित सबूत (जहाँ लागू हो) ;
- (ग) उपायुक्त शिमला के कार्यालय के सम्यक रूप से प्राधिकृत, अधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि सील्ड सड़क पर आवास किसी भी प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है और आवेदक का अपना गराज है और पार्किंग की उसके पास सुविधा है;
- (घ) नए आवेदन की दशा में प्रक्रिया फीस के संदाय का सबूत और पास के नवीकरण की दशा में पूर्व पास की एक फोटोप्रति;
- (ङ) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' की बाबत विधिमान्य प्रमाण पत्र की प्रति; और
- (च) ऐसे अन्य दस्तावेज जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(7) सभी आवेदन इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अभिस्वीकृत किए जाएंगे, रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और प्रक्रिया में लाए जाएंगे।

(8) सील्ड सड़क के लिए पास, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर ऐसे अधिकारी जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो, के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जारी किया जाएगा और पास का ऐसा सुभिन्न रंग और आकार होगा, जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए तथा पास को यान की विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यदि पास एक से अधिक सील्ड सड़क की बाबत जारी किया गया है, तो समेकित पास ऐसे प्ररूप में जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर जारी किया जा सकेगा ।

7. (1) प्रतिबंधित सड़क पर यान चलाने के लिए पास प्रदान करने हेतु आवेदन, ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को सम्बोधित (प्रेषित) किया जाएगा।

प्रतिबंधित सड़कों के लिए पास प्रदान करने और नवीकरण करने हेतु आवेदन तथा प्रक्रिया।

(2) प्रतिबन्धित सड़क पर यान चलाने हेतु पास के मामले की प्रक्रिया (प्रोसैसिंग) हेतु सरकारी यान के लिए सौ रुपए और निजी (प्राइवेट) यान के लिए पांच सौ रुपए की अप्रतिदेय प्रक्रिया (प्रोसैसिंग) फीस प्रभारित की जाएगी।

(3) सरकारी यान हेतु पास प्रदान करने के लिए एक हजार रुपए की फीस और निजी (प्राइवेट) यान हेतु पास प्रदान करने के लिए दो हजार रुपए की फीस प्रति सड़क, प्रतिवर्ष प्रभारित की जाएगी:

परन्तु लोकोपयोगी यानों से कोई भी फीस प्रभार्य नहीं होगी।

(4) प्रतिबन्धित सड़क पर यान चलाने हेतु पास को इसे जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा या मण्डलायुक्त शिमला के सहायक आयुक्त द्वारा, यदि इसलिए प्राधिकृत है, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर प्रतिवर्ष नवीकृत किया जा सकेगा और यदि इसकी विधिमान्यता अवधि के अवसान से पूर्व आवेदक द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन नहीं किया जाता है, तो पास व्यपगत हो जाएगा:

परन्तु यदि आवेदक साबित कर देता है कि समय के भीतर नवीकरण हेतु आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण थे तो पास प्रतिमास या उसके भाग के लिए दो सौ रुपए की विलम्ब फीस के साथ विहित फीस के संदाय पर नवीकृत किया जा सकेगा।

(5) सरकारी यान हेतु प्रतिबन्धित सड़क के लिए पास प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) यथास्थिति, सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राज्य सरकार या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण पत्र कि यान, यथास्थिति, सम्बद्ध उच्च पदस्थ या शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ सम्बद्ध है या लोकोपयोगी यान है;
- (ख) सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस प्रभाव का स्वयं का प्रमाणन (जहां लागू हो) कि कार्यालय या

आवास, यथास्थिति, सीलड या प्रतिबन्धित सड़क पर है और वह किन्हीं प्रतिबन्धित या अन्य सड़कों से सुगम्य नहीं है;

- (ग) नए आवेदन की दशा में प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) फीस के संदाय का सबूत और पास के नवीकरण की दशा में पूर्व पास की एक फोटो प्रति;
- (घ) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है' की बाबत विधिमान्य प्रमाणपत्र की प्रति; और
- (ङ) ऐसे अन्य दस्तावेज जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु उच्च पदस्थों और उन्हें सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यानों की बाबत आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामलों में रजिस्ट्रार जनरल या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आवेदन करेगा ।

(6) निजी (प्राइवेट) यान हेतु प्रतिबन्धित सड़क का पास प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) सबूत के तौर पर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति, की आवेदक यान का स्वामी है ;
- (ख) आवेदक के आवास का, यथास्थिति, सीलड या प्रतिबन्धित सड़क पर होने का स्वतः प्रमाणित सबूत (जहां लागू हो) ;
- (ग) उपायुक्त शिमला के कार्यालय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो) कि आवास, यथास्थिति, सीलड या प्रतिबन्धित सड़क पर है; और किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है तथा आवेदक का अपना गराज है या नियमित पार्किंग की उसके पास सुविधा है;
- (घ) नए आवेदन की दशा में प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) फीस के संदाय का सबूत और पास के नवीकरण की दशा में पूर्व पास की एक फोटोप्रति ;
- (ङ) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी 'प्रदूषण नियन्त्रण में है', की बाबत विधिमान्य प्रमाणपत्र की प्रति; और
- (च) ऐसे अन्य दस्तावेज जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) सभी आवेदन, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभिस्वीकृत किए जाएंगे, रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और प्रक्रिया में लाए जाएंगे।

(8) प्रतिबन्धित सड़क के लिए पास उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर, ऐसे अधिकारी जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो या सहायक आयुक्त, के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जारी किया जाएगा और पास का ऐसा सुभिन्न रंग और आकार होगा, जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए तथा पास को यान की विन्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु यदि पास एक से अधिक प्रतिबन्धित सड़क की बाबत जारी किया गया है, तो समेकित पास ऐसे प्ररूप में जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर जारी किया जाएगा।

8. (1) सील्ड सड़क के लिए अस्थायी पास, ऐसी शर्तों पर जो पास में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकारी समारोहों (औफिशियल फंक्शनज) आदि के कारण, राज्य के बाहर के उच्च पदस्थ व्यक्ति के सरकारी यान को और सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा यानों को या शासकीय महत्वपूर्ण व्यक्ति को, जो ऐसे स्थल पर भाग ले रहा है जो ऐसी सील्ड सड़क से ही सुगम्य हो और जहां स्थल, यथास्थिति, प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क से सौ मीटर से अनधिक की पथ दूरीस्वरूप सुगम्य न हो लोकहित में जारी किया जाएगा।

कतिपय परिस्थितियों में अस्थायी पास प्रदान करना।

(2) अस्थायी पास, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो पास में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे लोकोपयोगी यान को भी जारी किया जा सकेगा जिसका ऐसी सील्ड सड़कों पर चलाया जाना लोकहित में है।

(3) सील्ड सड़क के लिए अस्थायी पास का आवेदन, दो सौ रूपए प्रतिदिन प्रतियान की फीस के संदाय पर, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए, राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, कम से कम दो दिन अग्रिम में, समर्थक दस्तावेजों के साथ किया जाएगा और पास ऐसे प्ररूप में, जैसा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी अधिकारी, जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो, के हस्ताक्षरों और मुहर (मुद्रा) के अधीन जारी

किया जाएगा; और उक्त पास का ऐसा सुभिन्न रंग और आकार होगा, जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए ; और उसे यान की विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यदि पास एक से अधिक सील्ड सड़क के लिए जारी किया गया है, तो एक समेकित पास, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, धारा 6 की उपधारा (3) में यथा उपबंधित फीस के संदाय पर जारी किया जाएगा ।

(4) प्रतिबन्धित सड़क के लिए अस्थायी पास, राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को किए गए आवेदन पर, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसके समर्थन में दिए गए कारणों सहित, प्रतिदिन सौ रूपए की फीस के संदाय पर, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए इस शर्त के अधधीन कि यान को चलाए जाने से पैदल चलने वालों को कोई खतरा या क्षोभ कारित होने की संभावना न हो ; और उक्त पास का ऐसा सुभिन्न रंग और आकार होगा जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए और उसे यान की विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु यदि पास एक से अधिक प्रतिबन्धित सड़क के लिए जारी किया गया है, तो समेकित पास ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (3) में यथा उपबंधित फीस के संदाय पर जारी किया जाएगा ।

(5) फिल्मों के फिल्मांकन (शूटिंग) के प्रयोजनार्थ या किसी वाणिज्यिक मनोरंजन के प्रयोजनार्थ सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों के लिए अस्थायी पास राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा अधिकतम दस यानों तक प्रतिदिन, प्रतियान, तीन हजार रूपए की फीस के संदाय पर, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे:

परन्तु पैदल चलने वालों को किसी खतरे या क्षोभ से निवारित करने के लिए, पास को जारी करते समय इसकी विधिमान्यता के घण्टों और पार्किंग निर्बन्धनों के सम्बन्ध में शर्तें अधिरोपित की जा सकेंगी ।

(6) इस धारा के अधीन अस्थायी पास ,राष्ट्रीय स्तर के उच्च पदस्थों और उनके साथ चल रहे सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाए गए यानों को सामान्य प्रशासन विभाग के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर जारी किए जा सकेंगे ।

9. (1) शिमला शहर में आने वाला पर्यटक, ऐसे पर्यटन सुविधा केन्द्रों, जो गृह विभाग द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, पर प्रतिबन्धित सड़क के लिए पर्यटक पास हेतु आवेदन कर सकेगा । पर्यटक पास प्रदान करना ।

(2) पर्यटक पास, ऐसी शर्तों पर जैसी पास में विनिर्दिष्ट की जाएं, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए, प्रति प्रतिबन्धित सड़क, प्रतियान, प्रति दिन, सौ रूपए की फीस के संदाय पर इस शर्त के अधधीन जारी किया जा सकेगा कि यान चलाने से पैदल चलने वाले यात्रियों को खतरा या क्षोभ होना सम्भाव्य न हो ।

(3) पास का ऐसा सुभिन्न रंग तथा आकार होगा जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए और पर्यटक पास को यान की विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु पर्यटक पास को यदि एक से अधिक प्रतिबन्धित सड़क के लिए जारी किया गया है, तो एक समेकित पास ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित फीस के संदाय पर जारी किया जाएगा :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार जनहित में प्रतिबन्धित सड़कों पर पर्यटक अनुज्ञा-पत्रों की संख्या विनियमित कर सकेगी, जिसके लिए ऐसे अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकेगा ।

10. इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पास, निम्नलिखित साधारण निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उपान्तरित किया जा सकेगा, प्रदान किए जाएंगे:—

साधारण शर्तें ।

- (क) सील्ड या प्रतिबन्धित सड़कों पर बीस किलोमीटर प्रतिघण्टा से अधिक की गति से यान नहीं चलाए जाएंगे और यान द्वारा गतिसीमा के उल्लंघन का पता चलने पर उसका पास रद्द किए जाने के लिए दायी होगा;
- (ख) व्यक्ति जिन्हें सील्ड या प्रतिबन्धित सड़कों के लिए पास प्रदान किए गए हैं, अपने यान केवल निजी (प्राइवेट) परिसरों या अनुज्ञात पार्किंग स्थानों पर ऐसी रीति में खड़ा करेंगे ताकि यानों और पैदल चलने वाले दूसरे को क्षोभ या खतरा कारित न हो तथा सील्ड या प्रतिबन्धित सड़कों पर अप्राधिकृत रूप से या खतरनाक

तरीके से खड़े पाए गए यानों के पास रद्द किए जाने के लिए दायी होंगे ;

- (ग) किसी यान के स्वामी का सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क का पास धारण करना ही किसी भी रीति में उपर्युक्त सड़कों में से किसी पर भी यान खड़ा करने का अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा;
- (घ) यान, अनुज्ञात पार्किंग स्थानों और समादत्त पार्किंग स्थानों (पेड पार्किंग लॉट्स) के सिवाय सील्ड या प्रतिबन्धित सड़कों पर खड़े नहीं किए जाएंगे;
- (ङ) जिन यानों को सील्ड सड़कों के पास प्रदान किए गए हैं, सड़कों पर तभी चलाए जाएंगे यदि व्यक्ति, जिसके पक्ष में पास प्रदान किया गया है, स्वयं या उसका पति/उसकी पत्नी यान में बैठा हुआ है/बैठी हुई है या यदि यान चालक (शॉफर) द्वारा चलाया जाने वाला है, तो उसका चलाया जाना केवल पास धारक या उसके पति या पत्नी को लाने के आशय से होगा;
- (च) वैध पास यान की विण्ड स्क्रीन पर चिपकाए जाएंगे और पास धारक सील्ड या प्रतिबन्धित सड़कों पर, यातायात पुलिस को जांच स्थलों पर, पास की जांच करने के लिए यान की गति को धीमी करेगा या यान को रोकेगा;
- (छ) पास केवल अनुज्ञात सड़क पर विधिमान्यता अवधि के दौरान ही उपयोग में लाए जाएंगे;
- (ज) अवसित (समाप्त) पास प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे; और
- (झ) पास का दुरुपयोग, पास धारक के सभी या किन्हीं वैध पासों को रद्द करना अपरिहार्य बना देगा।

इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन।

11. उपायुक्त शिमला और पुलिस अधीक्षक शिमला सुनिश्चित करेगा कि :-

- (क) समस्त सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों के प्रवेश स्थलों और सहजदृश्य स्थलों पर संकेतों की व्यवस्था है जो सड़क का नाम और इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों को उपदर्शित करती है;
- (ख) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित करने के लिए विशेष रूप से व्यस्ततम समय पर पर्याप्त यातायात पुलिस तैनात (अभिनियोजित) की गई है;
- (ग) सील्ड सड़कों में प्रवेश और निकास तथा अन्य सामरिक (स्ट्रेटीजिक) स्थलों पर बैरियरों की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की

गई है कि यान ऐसी सड़कों का उपयोग आम रास्ते के रूप में या यान को अधिक गति से चलाने के लिए न करें ; और

- (घ) सील्ड या प्रतिबन्धित सड़कों पर चलने वाले यानों की निरन्तर अन्तरालों पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, स्थल पर (मौके पर) ही जांच (चैकिंग) की जा रही है।

12. (1) जो कोई पास के किसी भी निबन्धन और शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसे दो हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा या उसके व्यतिक्रम में उसे दस दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा: शास्तियां।

परन्तु ऐसे प्रत्येक अपराध का वर्दी में पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, एक हजार रूपए की प्रशमन फीस के साथ स्थल पर (मौके पर) ही शमन किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधधीन रहते हुए जो कोई इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसे तीन हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा या उसके व्यतिक्रम में उसे पन्द्रह दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा:

परन्तु यह कि वर्दी में पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पन्द्रह सौ रूपए की प्रशमन फीस के साथ अपराध का स्थल पर (मौके पर) ही शमन किया जा सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति प्रशमन फीस का संदाय करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उसकी चालन अनुज्ञप्ति सहित, परिबद्ध कर लिया जाएगा और मामले को अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा।

13. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट, अभियुक्त व्यक्ति पर तामील किए जाने वाले समन पर कथन करेगा कि वह:-

मामलों का संक्षिप्त निपटारा।

- (क) प्लीडर (अभिवक्ता) द्वारा या व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हो सकेगा; या

(ख) आरोप पर सुनवाई से पूर्व विनिर्दिष्ट तारीख तक आरोप का दोषी होने का अभिवचन कर सकेगा और न्यायालय को मनीआर्डर द्वारा अपराध के लिए विनिर्दिष्ट जुर्माना भेज सकेगा तथा दोषी होने का अभिवाक मनीआर्डर के कूपन में ही उपदर्शित कर सकेगा।

(2) यदि अपराध के होने के पन्द्रह दिन के भीतर अपराध का शमन नहीं होता है, जैसा इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन उपबन्धित है, तो वर्दी में पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दोषसिद्धि पर्ची (कनविक्शन स्लिप) के साथ परिवाद को प्रस्तुत करेगा, जो तत्पश्चात् अपराध होने के तीस दिन के भीतर उपधारा (1) के अधीन आगे कार्यवाही करेगा।

(3) न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने के पश्चात् दोषसिद्धि पर्ची (कानविक्शन स्लिप) को सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट को आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजेगा।

पासों का
रद्दकरण।

14. (1) यदि किसी पास धारक को पास के निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो धारा 12 के अधीन उपबन्धित किसी शास्ति के अतिरिक्त पास को राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा रद्द किया जा सकेगा :

परन्तु रद्दकरण का ऐसा कोई भी आदेश, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) उपायुक्त शिमला और पुलिस अधीक्षक शिमला पास धारक द्वारा इस अधिनियम के किसी अतिल्लंघन, जो पास को रद्दकरण के लिए दायी बनाता है, का पता चलने पर उसकी सूचना गृह विभाग को देगा।

(3) कोई व्यक्ति जिसका पास, पास के निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के कारण रद्द किया गया है, तो वह रद्दकरण आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसी यान के लिए, अपने नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से किसी भी पास को प्राप्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

अपील।

15. (1) न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील, अधिकारिता रखने वाले सत्र न्यायाधीश को, उक्त आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जा सकेगी।

(2) पास के रद्दकरण के विरुद्ध अपील, यथास्थिति, राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) या प्रधान सचिव (गृह) को, रद्दकरण आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर की जा सकेगी।

16. (1) ऐसी तारीख से, जैसी राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए सुख-सुविधा निधि” के नाम से एक निधि स्थापित की जाएगी।

फीस और जुर्मानों के आगमों का उपयोग।

(2) निधि राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन होगी और उसमें ऐसी धनराशि जमा की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध करवाई जाए और निधि में जमा अतिशेष वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत नहीं होगा।

(3) गृह विभाग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का वार्षिक विवरण ऐसी रीति में तैयार करेगा, जैसी विहित की जाए।

(4) निधि का, सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों के साथ पैदल चलने वालों की सुख-सुविधाओं, पैदल चलने वालों की सुरक्षा में सुधार, निवासियों के लिए रियायती दरों सहित सुविधाजनक पार्किंग स्थलों का विकास, प्रवेश नियन्त्रण और मॉनीटरिंग उपकरणों आदि के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा ताकि सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर यानीय गति को विनियमित किया जा सके तथा पैदल चलने वालों के संभाव्य खतरे या क्षोभ को कम किया जा सके।

(5) मण्डलायुक्त शिमला की अध्यक्षता वाली और आयुक्त नगर निगम शिमला, उपायुक्त शिमला तथा पुलिस अधीक्षक शिमला से समाविष्ट समिति, निधि को प्रशासित करेगी, और—

- (i) सील्ड या प्रतिबन्धित सड़कों को सम्मिलित करने या इनमें से इन्हें निकालने की सिफारिश कर सकेगी ;
- (ii) पार्किंग स्थानों के लिए स्थलों की सिफारिश कर सकेगी ;
- (iii) निधि में जमा धन के उपयोग के लिए प्रस्तावों को पास कर सकेगी और उनकी प्रगति मॉनीटर कर सकेगी ;

- (iv) इस अधिनियम के प्रवर्तन को मॉनीटर कर सकेगी ; और
- (v) ऐसे अन्य सम्बन्धित क्रियाकलाप कार्यान्वित कर सकेगी, जो विहित किए जाएं ।

(6) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत समस्त फीस और जुर्माने के आगम राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और यदि राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा इस प्रकार उपबन्धित करे निधि से ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लाए जाने हेतु विनियोजित किए जाएंगे ।

(7) निधि की लेखा परीक्षा, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के परीक्षक द्वारा की जाएगी।

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति।

17. राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची-1 या अनुसूची-2 में से, उनमें विनिर्दिष्ट ,किन्हीं सड़कों में किसी को सम्मिलित कर सकेगी या उनमें से किसी को निकाल सकेगी और तदुपरि उक्त अनुसूचियाँ तदनुसार संशोधित हो जाएंगी।

शिथिल करने की शक्ति।

18. राज्य सरकार ऐसे कारणों से, जो लिखित में अभिलिखित किए जाएंगे, लोकहित में, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को, लोगों के किसी भी वर्ग के लिए, या अनुसूची-1 और 2 में सम्मिलित किसी भी सड़क की बाबत, एक बार में सात दिन से अनधिक अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई भी शिथिलीकरण कोर (मध्य) माल रोड की बाबत नहीं किया जाएगा।

अधिकारिता का वर्जन।

19. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन आने वाले मामलों से सम्बन्धित प्रश्नों को ग्रहण करने या उनका विनिश्चय करने की कोई अधिकारिता या शक्ति नहीं होगी।

कठिनाईयों का दूर किया जाना।

20. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हों और जो इसे, कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

21. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि, उक्त सत्रों जिनमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपर्युक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या यह विनिश्चय करती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

22. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में ।

अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं ।

23. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध न होंगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

24. (1) गृह विभाग के पृष्ठांकन संख्या: गृह-सी (ई) 2-1/2000, तारीख 20 दिसम्बर, 2003 द्वारा सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर यातायात को विनियमित करने के लिए जारी की गई पॉलिसी गाइडलाइनज और इस निमित्त समय-समय पर जारी की गई अन्य गाइडलाइनज, अधिसूचाएं या आदेशों का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

निरसन और व्यावृत्तियाँ ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित पॉलिसी गाइडलाइनज, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची-1

(धारा 2 और 3 देखें)

सील्ड सड़कों की सूची

रोड कोड	सड़क का नाम
1	2
सील्ड 1.	छोटा शिमला चौक से ओक ओवर (माल रोड) तक ।
सील्ड 2.	ऑक ओवर से शिमला क्लब (माल रोड) तक ।
सील्ड 3.	इन्दिरा गान्धी अस्पताल की लोअर बाइफरकेशन से लक्कड़ बाजार तक ।
सील्ड 4.	जोधा निवास से रिट्ज तक ।
सील्ड 5.	होटल व्हाईट से रीगल सिनेमा तक ।
सील्ड 6.	कनैडी हाउस चौक से गॉर्टन कैसल (माल रोड) तक ।
सील्ड 7.	रेलवे बोर्ड भवन से सैनिक प्रशिक्षण कम्पण्ड (माल रोड) तक ।
सील्ड 8.	तारा हाल स्कूल से कालीबाड़ी की ओर और शिमला टाइपराईटर कम्पनी तक, माल रोड को जोड़ते हुए लिंक रोड ।
सील्ड 9.	स्कैण्डल प्वाइंट से कालीबाड़ी तक ।
सील्ड 10.	शैले डे स्कूल से यू0 एस0 क्लब और नीचे कम्बरमेयर पुल (उच्च न्यायालय से माल रोड को क्रॉस करते हुए) तक ।

टिप्पण:

- I. कोर माल रोड, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक में दी गई रीति में विनियमित किया जाएगा ।
- II. सील्ड 4 और सील्ड 5 सड़कों के लिए दिया गया पास, यान को रिज के आर-पार (अक्रास) चलाने के लिए हकदार नहीं बनाएगा ।

अनुसूची-2

(धारा 2 और 3 देखें)

प्रतिबन्धित सड़कों की सूची

रोड कोड	सड़क का नाम
1	2
प्रतिबंधित 1.	कनैडी हाउस चौक से, पुलिस स्टेशन चौक से पीटर हॉफ/ऑल इण्डिया रेडियो स्टेशन/भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (माल रोड) तक।
प्रतिबंधित 2.	पीटरहॉफ/ऑल इण्डिया रेडियो स्टेशन/भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से बालूगंज (माल रोड) तक।
प्रतिबंधित 3.	कार्ट रोड से उपायुक्त कार्यालय तक।
प्रतिबंधित 4.	कार्ट रोड से सब्जी मंडी तक।
प्रतिबंधित 5.	संजौली चौक से लोअर बाइफरकेशन इन्दिरा गांधी अस्पताल (लक्कड़ बाजार) तक।
प्रतिबंधित 6.	फॉरेस्ट लॉज (रामचन्द्र चौक) से वाया यू0एस0 क्लब, जोधा निवास तक।
प्रतिबंधित 7.	कार्ट रोड से गॉर्टन कैसल तक।

टिप्पण: निम्नलिखित सड़कें केवल छोटे यानों (लाइट व्हीकल्ज) के लिए खुली रहेंगी, जिनके लिए किसी अनुज्ञा-पत्र (परमिट) की आवश्यकता नहीं होगी :-

1. कार्ट रोड (मैडिकल कॉलेज की ओर) से इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज अस्पताल तक, लिंक रोड।
2. सेंट बीडज कॉलेज चौक से फॉरेस्ट लॉज तक।
3. कार्ट रोड से अग्निशमन उपकेन्द्र छोटा शिमला होते हुए, बैनमौर से ओक ओवर चौक तक [और माल रोड से ओक ओवर गेट के आर-पार (अक्रास)]।
4. कार्ट रोड (सेंट एडवर्ड स्कूल के पास) से मरीना होटल तक।
5. कार्ट रोड -अनाडेल, कनेडी हाउस चौक होते हुए।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पर्यटकों के लिए शिमला और उसके आस-पास के क्षेत्र आकर्षण के प्रमुख स्थान हैं और ऐतिहासिक तौर पर शिमला के मार्गों (स्ट्रीट्स) को प्रसिद्ध माल रोड सहित इस धारणा से विकसित किया गया कि इनका उपयोग मुख्यतः पैदल चलने के लिए किया जाएगा। पिछले कुछ समय से सरकारी और स्थानीय निवासियों तथा पर्यटकों, दोनों के निजी प्राइवेट यानों की अत्याधिक वृद्धि ने मार्गों (स्ट्रीट्स) को अति संकुलित कर दिया है तथा पैदल चलने वालों का आवागमन विशेषकर माल रोड में जिसका उपयोग असंख्य पैदल चलने वालों, पर्यटकों और स्कूली बच्चों द्वारा किया जा रहा है, कठिन तथा खतरनाक बना दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने तारीख 8.5.1991 को एक पॉलिसी बनाई। तत्पश्चात्, राज्य सरकार ने, सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 505/2000 नामतः “सिटीजन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य” में कार्यवाहियों के दृष्टिगत शिमला नगर में यानीय यातायात के विनियमन हेतु प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए पॉलिसी को पुनः प्रतिपादित किया। तदनुसार तारीख 20-12-2003 को पॉलिसी जारी की गई जिसमें अन्य पैरामीटरों, जिनमें अनुज्ञा-पत्र (परमिट) प्रदान करने हेतु दिए गए आवेदनों की संवीक्षा करते समय और उसमें अनुज्ञा-पत्र (परमिट) धारकों द्वारा शर्तों को विहित करते समय ध्यान में रखना अपेक्षित था सहित, एक नई अनुज्ञा-पत्र (परमिट) फीस संरचना की व्यवस्था की गई थी।

वर्ष 2005 में, क्रमशः सी.डब्ल्यू.पी. संख्या: 739/2005 और पी.आई. एल. संख्या: 9/2005 नामतः “अंकुश दास सूद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य” तथा “किशन सिंह वर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य” माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थीं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न अभिकरणों द्वारा शिमला शहर में सील्ड/प्रतिबन्धित सड़कों के लिए अनुज्ञा-पत्रों (परमिटों) को जारी करने के सम्बन्ध में और अन्य सहबद्ध विषयों, जैसे कि विभिन्न सड़कों/विनिर्दिष्ट स्थानों पर यानों को खड़ा करने (पार्किंग), उक्त सड़कों पर यानों को अधिक गति से चलाने (ओवरस्पीडिंग) तथा अप्राधिकृत चालन आदि के सम्बन्ध में निदेश मांगे गए थे। राज्य सरकार ने, सी.डब्ल्यू.पी. संख्या: 739/2005 में तारीख 28-09-2005 को किए गए आदेशों के अनुसरण में तारीख 10-11-2005 और 14-12-2005 के शपथ पत्रों के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मोटरयान अधिनियम की धारा 115 के अधीन जारी की जाने वाली प्रारूप अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें विशेषतः यह प्रकथन किया गया कि इसे जारी करने से पूर्व मन्त्रिपरिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। मामले पर मन्त्रिपरिषद् द्वारा तारीख 21-2-2006 और 14-3-2006 की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि अधिसूचना को जारी करने के बजाए इस विषय पर एक विधान लाया जाए जिसमें उन उपबन्धों को सम्मिलित किया जाए जो प्रारूप अधिसूचना में पूर्वतर प्रस्तावित किए गए थे।

यह विधान सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों को परिभाषित करने और विहित शर्तों पर ऐसी सड़कों पर यान चलाने के लिए फीस के संदाय पर पासों को प्रदान करने के निबन्धनों का उपबन्ध करने के लिए है। पैदल चलने वालों तथा यानों के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए “शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए सुख-सुविधा निधि” के नाम से एक निधि का गठन भी प्रस्तावित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्यमन्त्री।

शिमला:

तारीख.....2007

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे। इसलिए राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 21 राज्य सरकार को, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) विधेयक, 2007

शिमला माल रोड की पहचान (महत्व), आम रास्ते के रूप में इसके उपयोग को रोकते हुए, पुनः लौटाने, शिमला नगर की सीलड और प्रतिबन्धित सड़कों पर, लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में, पैदल चलने वालों को क्षोभ और क्षति से निवारित करने हेतु, यानीय यातायात को विनियमित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक** ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्यमन्त्री ।

जे० एन० बारोवालिया,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला:

तारीख:.....2007

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) BILL, 2007**ARRANGEMENT OF CLAUSES*****Clauses:***

1. Short title, extent and commencement.
 2. Definitions.
 3. Restrictions on the use of vehicles on sealed and restricted roads.
 4. Issue of passes.
 5. Exemption in certain cases.
 6. Application for grant and renewal of a pass for sealed roads and procedure.
 7. Application for grant and renewal of a pass for restricted roads and procedure.
 8. Grant of temporary passes in certain circumstances.
 9. Grant of tourist pass.
 10. General Conditions.
 11. Enforcement of provisions of this Act.
 12. Penalties.
 13. Summary disposal of cases.
 14. Cancellation of passes.
 15. Appeal.
 16. Utilization of the proceeds of the fee and fines.
 17. Power to amend Schedules.
 18. Power to relax.
 19. Bar of jurisdiction.
 20. Removal of difficulties.
 21. Power to make rules.
 22. Application of other laws not barred.
 23. Protection of action taken in good faith.
 24. Repeal and savings.
- Schedules.

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) BILL, 2007

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to restore the sanctity of the Shimla Mall Road by preventing its use as an thoroughfare and to provide for regulation of vehicular traffic in the interest of public safety and convenience on the sealed and restricted roads of Shimla town to prevent annoyance and injury to pedestrians and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007.

Short title,
extent and
commence-
ment.

(2) It extends to the Municipal limits of Shimla Town.

(3) It shall come into force at once.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) ‘Assistant Commissioner’ means Assistant Commissioner, appointed by the State Government under section 9 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953;
- (b) ‘Core Mall Road’ means the portion of the Mall Road from Shimla Club to Central Telegraph Office;
- (c) ‘Deputy Commissioner’ means the Chief Officer-in-charge of the general administration of a District;
- (d) ‘Divisional Commissioner’ means the Divisional Commissioner of Shimla Revenue Division;
- (e) ‘former High Dignitary’ means any person who has held at any time any of the offices of High Dignitary of the State;

-
- (f) 'former Official Personage' means any person who has held at any time any of the offices of official personage;
- (g) 'fund' means the "Shimla Road Users and Pedestrian Amenities Fund" established under section 16 of this Act;
- (h) 'Head of Department' means the authority specified in Schedule –I to the Delegation of Financial Powers Rules, 1978 and includes such other authority or person as the State Government may, by order, specify as the Head of a Department;
- (i) 'Head of Office' means a Gazetted Officer declared as such under Rule 14 of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, and includes such other authority or person as the competent authority may, by order, specify as the Head of Office;
- (j) 'High Dignitary' means,—
- (i) The Governor of Himachal Pradesh;
 - (ii) The Chief Minister of Himachal Pradesh;
 - (iii) The Speaker of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly;
 - (iv) The Chief Justice of Himachal Pradesh High Court;
 - (v) Ministers of Himachal Pradesh;
 - (vi) Judges of Himachal Pradesh High Court; and
 - (vii) Deputy Speaker of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly;
- (k) 'Mall Road' means the road extending from Chhota Shimla Chowk to Boileauganj via Oakover, Shimla Club, Metropole Hotel, the Core Mall Road, Central Telegraph Office, Gorton Castle and Indian Institute of Advanced Studies;
- (l) 'Official Personage' means,—
- (i) the Members of Parliament from Himachal Pradesh and Members of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh;
 - (ii) Chief Secretary/Additional Chief Secretary to the State Government;

-
- (iii) The Advocate General of Himachal Pradesh;
 - (iv) General Officer Commanding- in Chief, Army Training Command, Shimla;
 - (v) Central or State Government officers and officers of the State judiciary, in Super Time Scale or above, posted in Shimla;
 - (vi) the Military Officers of the rank of Major- General and above, posted in Shimla;
 - (vii) the Mayor, Deputy Mayor and Councilors, Municipal Corporation, Shimla; and
 - (viii) Full time Chairmen and Members of Boards, Corporations or Statutory Commissions of Himachal Pradesh, in Super Time Scale and above;
- (m) 'pass' means a pass issued under this Act for driving of a vehicle on a sealed or restricted road, or both, as the case may be;
- (n) 'Prescribed' means prescribed by rules made under this Act;
- (o) 'Public utility vehicles' means the following vehicles, used or being used for carrying out essential service:—
- (i) Fire fighting vehicles;
 - (ii) Ambulances and dead body vans;
 - (iii) Postal Mail vehicles;
 - (iv) Vehicles deployed for maintenance of communications and other public services and public transport vehicles approved by Home Department;
 - (v) Vehicles deployed for maintenance of sanitation, water supply and other civic services by the Municipal Corporation, Shimla including official vehicles approved by the Home Department and to be used by the Municipal Corporation officers for day-to-day inspection and maintenance of the said duties;
 - (vi) Heavy vehicles belonging to the Central Public Works Department, Himachal Pradesh Public Works Department, Himachal Pradesh State Electricity Board, Irrigation and Public Health Department and Municipal Corporation Shimla etc. deployed for execution of any construction or maintenance activities;

- (vii) Official vehicles required for law and order and for protocol duty with High Dignitaries by the District Administration, Shimla and the General Administration Department of the State Government; and
- (viii) Security Vehicles provided by the Government for the protection of a High Dignitary, carrying security personnel and accompanying the High Dignitary.

- (p) 'restricted road' means a road specified in Schedule-II;
- (q) 'Schedule' means a Schedule appended to this Act;
- (r) 'sealed road' means a road specified in Schedule-I;
- (s) 'State' means the State of Himachal Pradesh;
- (t) 'State Government' means the Government of Himachal Pradesh;
- (u) 'Super time scale' means the pay scale of Rs.18400 - Rs.22400; and
- (v) 'temporary pass' means a pass issued under section 8 of the Act; and
- (w) 'tourist pass' means a pass issued under section 9 of the Act.

(2) All other words and expressions used, but not defined in this Act and defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), shall have the same meaning respectively assigned to them in that Act.

Restrictions
on the use of
vehicles on
sealed and
restricted
roads.

3. (1) All sealed roads specified in Schedule-I shall be sealed to all motorized traffic, except the following vehicles, namely:—

- (i) One official vehicle of each High Dignitary and accompanying officially provided security vehicles;
- (ii) One vehicle each of the former Chief Ministers of the State;
- (iii) public utility vehicles as deemed necessary in the public interest by the Secretary (Home) to the State Government;
- (iv) One official vehicle of an Official Personage or one vehicle of a former High Dignitary for plying on one sealed road provided that permit for the Chhota Shimla to High Court via Oakover portion of the Mall Road may be given only if he has his residence or official work place on such road and such residence or official work place is not approachable from a restricted road or other road;

- (v) One vehicle owned by a property tax payer of a residential property or a High Dignitary or an Official Personage having residence on a sealed road, provided it is not approachable from a restricted or other road, and there is a garage/ parking facility on such residential property; and
- (vi) Vehicles holding a valid temporary pass issued under section 8 of the Act:

Provided that no vehicle other than public utility vehicle shall be permitted to ply on the Core Mall Road, except vehicles of President of India, Vice-President of India, Prime Minister of India, the Governor of Himachal Pradesh and the Chief Minister, Himachal Pradesh and their accompanying officially provided security vehicles:

Provided further that the Secretary (Home) may, from time to time, impose restrictions on the maximum width (wheel base) of a vehicle for any sealed road in the interest of public safety and convenience so as to prevent hindrance to cross movement of traffic.

Explanation.—For the purposes of this Act a residence shall be deemed to be approachable through a restricted road or any other road, as the case may be, if it is situated within path distance of 100 meters from such road.

(2) All restricted roads specified in Schedule-II shall be closed to all motorized traffic, except the following vehicles, namely:—

- (i) One official vehicle of each High Dignitary and their accompanying officially provided security vehicles;
- (ii) One vehicle each of the former Chief Ministers of the State;
- (iii) Public utility vehicles as deemed necessary in the public interest by Secretary (Home) to the State Government;
- (iv) One official vehicle earmarked for the use of an Official Personage, for up to 3 such roads, plying on which is in the public interest;

- (v) One private vehicle owned by a High Dignitary or Official Personage or former High Dignitary or former Official Personage or a State Level Press Correspondent accredited by the Accreditation Committee of the State Government, for not more than 3 such roads;
- (vi) Upto two vehicles in respect of a Hotel or other boarding place, not approachable from any other road, in order to carry guests from designated parking places or paid parking lots; provided that the vehicle is owned or leased by the Hotel/boarding place for a period of not less than 3 months;
- (vii) One vehicle in respect of a house-owner or occupier ordinarily resident in a property to provide access through a restricted road where the property is not approachable from any un-restricted road;
- (viii) Official vehicles attached to Central or State Government offices located on sealed or restricted roads, in order to provide reasonable transport access upto that office through a convenient restricted road, in case the office is not approachable from any other road;
- (ix) Vehicles holding a valid temporary pass issued under section 8 of the Act; and
- (x) Vehicles holding a valid tourist pass issued under section 9 of the Act.

Explanation.—For the purposes of this Act, a place shall be deemed to be approachable through any other road, if it is situated within a distance of 100 meters from such road.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, the Secretary (Home) to the State Government, may specify the maximum number of vehicles that may be allowed to ply on a particular restricted road keeping in view the quantum of traffic and nature of road, so as not to cause danger, inconvenience or annoyance to the pedestrians.

4. (1) Vehicles shall be allowed to use roads specified in Schedule-I or II on grant of a 'pass' by the State Government in the manner provided in this Act, subject to restrictions specified under section 3 and on general conditions specified under section 10 of the Act:

Issue of
Passes.

Provided that no vehicle shall be granted a pass unless it has a valid 'Pollution under Control Certificate' issued by the concerned authority.

(2) The pass shall be granted to provide access to residence or to an official work place in the public interest and shall be for only that portion of the sealed or restricted road that is reasonably required to access the nearest other road.

(3) Where the maximum number of passes has been fixed for a restricted road, preference may be given to,—

- (a) senior citizens and permanently disabled; and
- (b) those with garages/parking places / drive ways or other regular parking arrangement.

(4) Not more than one pass shall be issued per family or residence on the grounds of residence on a sealed or restricted road, and the mere fact that the residence or official work place is on a sealed or restricted road shall not entitle the grant of a pass.

5. No pass shall be required to drive a motor vehicle between 11.00 PM and 7.00 AM on a restricted road:

Exemption
in certain
cases.

Provided that Government in order to prevent annoyance or danger to vehicles and pedestrians may impose such reasonable restrictions (including declaration of roads as one way or no traffic roads for specified times of the day) in respect of any sealed or restricted road as may be necessary having regard to the circumstances of a particular sealed or restricted road.

6. (1) Application for grant of a pass for driving a vehicle on a sealed road shall be made in such form as may be specified by notification, and shall be addressed to the Under Secretary (Home) to the State Government.

Application
for grant
and renewal
of a pass for
sealed road
and
procedure.

(2) A non-refundable fee of Rs.100 for an official vehicle and Rs.500 for a private vehicle shall be charged for processing of case for a pass for driving of a vehicle on a sealed road.

(3) A fee of Rs.1000 shall be charged for grant of a pass for an official vehicle and Rs.2500 for grant of a pass for a private vehicle per road, per annum:

Provided that no fee shall be chargeable in respect of public utility vehicles.

(4) The pass for driving a vehicle on a sealed road may be renewed annually by the Home Department on payment of a fee as provided in sub-section (3) and in case the applicant does not make an application for renewal before the expiry of its validity period, the pass shall stand lapsed:

Provided that if the applicant proves that there were sufficient reasons for not making an application for renewal in time, the pass may be renewed on payment of fee as provided in sub-section(3) alongwith late fee of Rs.200 per month or part thereof.

(5) The application for grant or renewal of a pass for an official vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) A certificate from Secretary (General Administration Department) to the State Government or the Head of the Office, as the case may be, to the effect that the vehicle is deployed with the High Dignitary or Official Personage concerned; or is a public utility vehicle, as the case may be;
- (b) Self certification (where applicable) by the applicant to the effect that the office/residence is on a sealed road and is not approachable from any of the restricted or any other roads;
- (c) Proof of payment of the processing fee in case of a new application and a photocopy of the previous pass in case of renewal of a pass;
- (d) Copy of a valid 'Pollution under Control' Certificate issued by the concerned authority; and
- (e) Such other documents as may be specified, by notification:

Provided that in respect of High Dignitaries and their officially provided security vehicles, the application shall be made by an authorized officer of the General Administration Department, except in the case of the Judges of the High Court in respect of which the Registrar General or an officer authorized in this behalf shall make the application.

(6) The application for grant or renewal of a pass for a private vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) Attested photocopy of the Registration Certificate of the vehicle in proof that the applicant is the owner of the vehicle;
- (b) Self certified proof (where applicable) of residence of the applicant on the sealed road;
- (c) Certificate (where applicable) from the duly authorized officer of the office of the Deputy Commissioner, Shimla to the effect that the residence on the sealed road is not approachable from any other road and that the applicant has his own garage or has a parking facility;
- (d) Proof of payment of processing fee in case of a new application, and a photocopy of the previous pass in case of renewal of a pass;
- (e) Copy of a valid 'Pollution under Control' Certificate issued by the concerned authority; and
- (f) Such other documents as may be specified, by notification.

(7) All applications shall be acknowledged, registered and processed under the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(8) A pass for a sealed road shall be issued, in such form as may be specified by notification, under the signatures and seal of an officer not below the rank of Under Secretary (Home) to the State Government on payment of fee as provided in sub-section (3) and the pass shall have a distinct colour and shape, as may be determined by the Home Department from time to time; and the pass shall be displayed on wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued in respect of more than one sealed road, a consolidated pass may be issued on payment of fee as provided in sub-section(3), in such form, as may be specified by a notification.

Application
for grant and
renewal of a
pass for
restricted
roads and
procedure.

7. (1) An application for grant of a pass for driving a vehicle on a restricted road shall be made, in such form as may be specified by notification, addressed to the Under Secretary (Home) to the State Government.

(2) A non-refundable fee of Rs.100 for an official vehicle and Rs.500 for a private vehicle shall be charged for processing of a case for a pass for driving of a vehicle on a restricted road.

(3) A fee of Rs. 1000 shall be charged for grant of a pass for an official vehicle and Rs.2000 shall be charged for grant of a pass for a private vehicle, per road, per annum:

Provided that no fee shall be chargeable in respect of public utility vehicles.

(4) The pass for driving a vehicle on a restricted road may be renewed annually by the issuing authority or by Assistant Commissioner to Divisional Commissioner, Shimla if so authorized, on payment of the fee as provided in sub-section (3) and in case the application for renewal is not made by the applicant before the expiry of its validity period, the pass shall stand lapsed:

Provided that if the applicant proves that there were sufficient reasons for not making an application for renewal in time, the pass may be renewed on payment of fee as provided in sub-section (3) alongwith a late fee of Rs.200 per month or part thereof.

(5) The application for grant or renewal of a pass for a restricted road for an official vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) A certificate by the Secretary (General Administration Department) to the State Government or the Head of the Office, as the case may be, to the effect that the vehicle is attached with the concerned High Dignitary or Official Personage or is a public utility vehicle, as the case may be;

- (b) Self-Certification (where applicable) by the Secretary (General Administration Department) or the Head of the Office to the effect that the office or residence is on a sealed or restricted road, as the case may be, and is not approachable from any of the restricted or any other roads;
- (c) Proof of payment of processing fee in case of a new application and a photocopy of the previous pass in case of renewal of a pass;
- (d) Copy of a valid 'Pollution under Control' Certificate issued by the concerned authority; and
- (e) Such other documents as may be specified, by notification:

Provided that in respect of High Dignitaries and their officially provided security vehicles, application shall be made by an authorized officer of the General Administration Department, except in cases of Judges of the High Court in respect of which the Registrar General or an officer authorized in this behalf, shall make the application.

(6) The application for grant or renewal of a pass for a restricted road for a private vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) Attested photocopy of the Registration Certificate of the vehicle in proof that the applicant is the owner of the vehicle;
- (b) Self Certified proof (where applicable) of residence of the applicant on sealed or restricted road, as the case may be;
- (c) Certificate (where applicable) from the duly authorized officer of the office of the Deputy Commissioner, Shimla to the effect that the residence on the sealed or restricted road, as the case may be, is not approachable from any other road and that the applicant has his own garage or has a facility of a regular parking place;
- (d) Proof of payment of processing fee in case of a new application, and a photocopy of the previous pass in case of renewal of a pass;
- (e) Copy of a valid 'Pollution under Control' Certificate issued by the concerned authority; and
- (f) Such other documents as may be specified, by notification.

(7) All applications shall be acknowledged, registered and processed under the provisions of this Act.

(8) A pass for a restricted road shall be issued, in such form as may be specified by notification, under the signatures and seal of an officer not below the rank of Under Secretary (Home) to the State Government or Assistant Commissioner, on payment of fee as provided in sub-section (3) and the pass shall have a distinct colour and shape, as may be determined by the Home Department from time to time; and shall be displayed on the wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued in respect of more than one restricted road, a consolidated pass shall be issued on payment of fee as provided in sub-section(3) in such form as may be specified by notification.

Grant of temporary passes in certain circumstances.

8. (1) A temporary pass may be issued on such conditions as may be specified in the pass, in the public interest for a sealed road on account of official functions etc. to the official vehicle of a High Dignitary from outside the State and accompanying officially provided security vehicles or to the official vehicle of an Official Personage attending an official function at a venue approachable only from such sealed road and where the venue is not approachable by way of path distance not exceeding 100 meters from a restricted road or any other road, as the case may be.

(2) A Temporary pass may also be issued to a public utility vehicle whose plying on such sealed roads is in the public interest, on such terms and conditions as may be specified in the pass.

(3) A temporary pass for a sealed road may be issued on payment of fee of Rs.200 per day per vehicle for maximum period of seven days, on application made to the Under Secretary (Home) to the State Government in such form as may be specified by notification, at least 2 days in advance with supporting documents, and the pass shall be issued in such form as may be specified by a notification issued from time to time, under the signatures and seal of an officer not below the rank of the Under Secretary (Home) to the State Government; and the said pass shall have a distinct colour and shape, as determined by the Home Department from time to time; and the same shall be displayed on the wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued for more than one sealed road, a consolidated pass shall be issued on payment of fee as provided in sub-section(3) of section 6 in such form as may be specified by notification.

(4) A temporary pass for a restricted road may be issued on payment of a fee of Rs.100 per day, for a maximum period of 7 days, on an application made to the Under Secretary (Home) to the State Government in such form as may be specified by notification, with reasons in support thereof, subject to the condition that the plying of the vehicle is not likely to cause danger or annoyance to pedestrians; and the said pass shall have a distinct colour and shape, as determined by the Home Department from time to time and the same shall be displayed on the windscreen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued for more than one restricted road, a consolidated pass shall be issued on payment of fee as provided in sub-section (3) in such form as may be specified by notification.

(5) Temporary passes for sealed and restricted roads for the purpose of shooting of films or for any commercial or entertainment purpose may be granted by the Secretary (Home) to the State Government for a maximum period of 7 days on payment of a fee of Rs.3000 per day per vehicle up to a maximum of 10 vehicles:

Provided that in order to avoid danger or annoyance to pedestrians, conditions may be imposed while granting a pass, in relation to the hours of its validity and parking restrictions.

(6) Temporary passes under this section may be issued to vehicles of National Level High Dignitaries and their accompanying officially provided vehicles on the basis of an application made by an authorized officer of the General Administration Department.

9. (1) A tourist visiting Shimla Town may apply for a restricted road tourist pass at such tourist facilitation centers as may be specified by Home Department by a notification from time to time.

Grant of
tourist
pass.

(2) A tourist pass may be issued, on such conditions as may be specified in the pass on payment of fee of Rs. 100/- per day per vehicle per restricted road for a maximum period of 7 days subject to the condition that the plying of vehicle is not likely to cause danger or annoyance to pedestrians.

(3) The pass shall have a distinct colour and shape, as may be determined by the Home Department from time to time and the tourist pass shall be displayed on window screen of the vehicle:

Provided that if a tourist pass is issued for more than one restricted road, a consolidated pass shall be issued on payment of fee as provided in sub-section(3), in such form as may be specified by a notification:

Provided further that the State Government may in the public interest regulate the number of tourist permits on the restricted roads for which such permit can be issued.

General
conditions.

10. Save as otherwise provided in this Act, passes shall be granted on the following general terms and conditions, which may be modified by the State Government, by notification:—

- (a) Vehicles shall not ply on the sealed or restricted roads at a speed of more than 20 K.M. per hour and the pass of a vehicle detected violating the speed limit shall be liable to be cancelled;
- (b) Persons granted sealed or restricted road passes shall park their vehicles in private premises or at permitted parking places only and in a manner so as not to cause annoyance or danger to other vehicles and pedestrians and passes of vehicles found unauthorizedly or dangerously parked along sealed or restricted roads shall be liable to be cancelled;
- (c) Mere holding of a sealed or restricted road pass by a vehicle owner shall not in any manner confer any right of parking a vehicle on any of the said roads;
- (d) Vehicles shall not be parked on sealed or restricted roads except at permitted parking places and paid parking lots;
- (e) Vehicles granted sealed road passes shall ply only when the person in favour of whom the pass is granted or his spouse is seated in the vehicle or in case the vehicle is a chauffeur driven vehicle, plying in order to pickup the pass holder or spouse;

- (f) Valid passes shall be pasted to the windscreen of the vehicle and the pass holder shall slow down or stop the vehicle at check points on the sealed or restricted roads to enable traffic police to inspect the pass;
- (g) Passes shall be used only on the permitted road and only during validity period;
- (h) Expired passes shall not be displayed; and
- (i) Misuse of pass shall entail cancellation of all or any valid passes of the pass holder.

11. The Deputy Commissioner, Shimla and Superintendent of Police, Shimla shall ensure,—

Enforcement of provisions of this Act.

- (a) Provision of signages at entry points and other conspicuous places on all sealed and restricted roads indicating the name of the road and the relevant provisions of this Act;
- (b) Deployment of sufficient traffic police, specially at peak hours in order to enforce the provisions of this Act;
- (c) Placement of Barriers at the entry and exit and other strategic points on sealed roads to ensure that vehicles do not use such roads as thoroughfares or drive at high speed; and
- (d) On the spot-checking, at frequent intervals, of the vehicles plying on the sealed or restricted roads, by an Executive Magistrate or Police Officer not below the rank of Sub-Inspector.

12. (1) Whoever contravenes any of the terms and conditions of the pass, shall be punishable with a fine of Rs.2000 or undergo simple imprisonment of 10 days in default thereof:

Penalties.

Provided that each such offence may be compounded on the spot by a Police Officer in uniform not below the rank of Sub-Inspector for a compounding fee of Rs. 1000.

(2) Subject to sub-section (1), whoever contravenes any of the provisions of this Act, shall be punishable with a fine of Rs.3000 or undergo simple imprisonment of 15 days, in default thereof:

Provided that a police officer in uniform not below the rank of Sub-Inspector may compound the offence on the spot for a compounding fee of Rs. 1500.

(3) If any person fails to pay the compounding fee, the Registration Certificate of the vehicle shall be impounded alongwith the Driving License of such person and the case shall be forwarded to the Judicial Magistrate, having jurisdiction.

Summary
disposal of
cases.

13. (1) The Judicial Magistrate taking cognizance of any offence under this Act, shall state upon the summons to be served on the accused person that he—

- (a) may appear by pleader or in person; or
- (b) may, by specified date prior to the hearing of the charge, plead guilty to the charge and remit to the Court, by money order, the fine specified for the offence, and the plea of the guilt indicated in the money order coupon itself.

(2) If the offence is not compounded, within 15 days of the commission of offence, as provided under section 12 of this Act, the police officer in uniform shall present the complaint alongwith conviction slip in the court of Chief Judicial Magistrate or the Judicial Magistrate, having jurisdiction, who shall, thereafter, within 30 days of the commission of offence, proceed further under sub-section(1).

(3) The Court after having convicted the accused person of an offence under this Act, shall send the conviction slip to the District Magistrate concerned for taking further necessary action.

Cancellation
of passes.

14. (1) If a pass holder is detected violating the terms and conditions of a pass, in addition to any penalty provided under section 12, the Secretary (Home) to the State Government may cancel the pass:

Provided that no such order of cancellation shall be passed without affording a reasonable opportunity of being heard.

(2) The Deputy Commissioner, Shimla and Superintendent of Police, Shimla, shall intimate the detection of any infringement of this Act, by a pass holder, which makes a pass liable for cancellation, to the Home Department.

(3) A person whose pass has been cancelled for violation of terms and conditions of the pass shall not be eligible for grant of any pass in his name or in the name of any family member for the same vehicle within one year from the date of the cancellation order.

15. (1) An appeal against the order of the Judicial Magistrate may be made to the Sessions Judge having jurisdiction, within 30 days from the date of the said order. Appeal.

(2) An appeal against cancellation of a pass may be made to the Additional Chief Secretary (Home) or the Principal Secretary (Home) to the State Government, as the case may be, within 15 days from the date of the cancellation order.

16. (1) With effect from such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be established for the purposes of this Act, a fund to be called “the Shimla Road Users and Pedestrians Amenities Fund”. Utilization of the proceeds of the fee and fines.

(2) The fund shall be under the control of the State Government and there shall be credited thereto any sums of money as may be provided by the State Government for carrying out the purpose of this Act, and the balance to the credit of the fund shall not lapse at the end of the financial year.

(3) The Home Department shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such manner as may be prescribed.

(4) The fund shall be used for the development of pedestrian amenities along sealed and restricted roads, improvement of pedestrian safety, development of convenient parking places with concessional rates for residents, access control and monitoring equipment etc., in order to regulate vehicular movement on sealed and restricted roads and reduce the likelihood of danger or annoyance to the pedestrians.

(5) A Committee headed by the Divisional Commissioner, Shimla and comprising of Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, Deputy Commissioner, Shimla and Superintendent of Police Shimla, shall administer the Fund, and may—

- (i) make recommendations on inclusion or deletion of roads from sealed or restricted roads;
- (ii) recommend sites for parking places;
- (iii) clear proposals for utilization of moneys credited in the Fund and monitor progress;
- (iv) monitor the enforcement of this Act; and
- (v) carryout such other related activities as may be prescribed.

(6) Proceeds of all fees and fines collected under this Act shall be credited to the Consolidated Fund of the State and shall be appropriated, if the State Legislature by law so provides, to the fund in such manner as may be prescribed, for being utilized exclusively for the purpose of the Act.

(7) The fund shall be audited by the Examiner of the local audit Department.

Power to
amend
Schedules.

17. The State Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, add to or delete from Schedule-I or Schedule-II any of the roads specified therein and thereupon the said Schedule shall stand amended accordingly.

Powers to
relax.

18. The State Government may, in the public interest, relax any of the provisions of this Act, for any class of persons or in respect of any road included in Schedules-I and II, for reasons to be recorded in writing, for a period not exceeding seven days at a time:

Provided that no such relaxation shall be made in respect of the Core Mall Road.

Bar of
jurisdiction.

19. No civil court shall have any jurisdiction or power to entertain or decide questions relating to matters falling under this Act.

20. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Removal of difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of one year of the coming into force of this Act.

21. (1) The State Government may, by notification, make rules consistent with this Act for carrying out the provisions of this Act.

Power to make rules.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session, for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before expiry of the sessions in which it is so laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

22. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of, the provisions of any other laws for the time being in force.

Application of other laws not barred.

23. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

24. (1) The policy guidelines to regulate traffic on sealed and restricted roads issued vide Home Department endorsement number Home-C(E)-2-1/2000, dated the 20th December, 2003 and any other guidelines, notifications or orders issued in this behalf, from time to time, are hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the policy guidelines, notifications or orders so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

Schedule-I
(See sections 2 and 3)

LIST OF SEALED ROADS

Road Code	Name of road
1	2
S-1.	From Chhota Shimla Chowk to Oakover, (Mall Road).
S-2.	From Oakover to Shimla Club (Mall Road).
S-3.	From lower bifurcation of Indira Gandhi Hospital to Lakkar Bazar.
S-4.	From Jodha Niwas to Ritz.
S-5.	From Hotel White to Regal Cinema.
S-6.	Kennedy House Chowk to Gorton Castle. (Mall Road).
S-7	Railway Board Building to Army Training Command (Mall Road).
S-8.	Link road from Tara Hall School Crossing towards Kalibari and upto Shimla Typewriter Company connecting the Mall Road.
S-9.	Scandal Point to Kalibari.
S-10.	Chalet Day School to U.S. Club and down upto Combermere Bridge(crossing Mall Road from High Court).

Note:—

- I. The Core Mall Road shall be regulated in the manner given in proviso to sub-section(1) of section 3 of the Act.
- II . The grant of a pass for roads S-4 and S-5 shall not entitle the vehicle to ply across the Ridge.

Schedule-II

(See sections 2 and 3)

LIST OF RESTRICTED ROADS

Road Code	Name of road
1	2
R-1.	From Kennedy House Chowk to Police Station Chowk to Peterhoff/All India Radio Station/Indian Institute of Advanced Studies (Mall Road).
R-2.	Peterhoff / All India Radio Station/Indian Institute of Advanced Studies to Boileauganj(Mall Road).
R-3.	From Cart Road to Deputy Commissioner Office.
R-4.	From Cart Road to Sabji Mandi.
R-5.	From Sanjauli Chowk to lower bifurcation Indira Gandhi Hospital (Lakkar Bazar).
R-6.	From Forest Lodge(Ramchandra Chowk) to Jodha Niwas via U.S.Club.
R-7.	From Cart Road to Gorton Castle.

Note.—The following roads are open for only light vehicles for which no permit is required:—

1. Link Road from Cart Road(Medical College side) to IGMCH Hospital.
2. From St.Bedes College Chowk to Forest Lodge.
3. From Cart Road via Fire Sub-Station Chhota Shimla, Benmore to Oakover Chowk (and across the Mall Road to Oakover Gate).
4. From Cart Road(near St. Edwards School) to Marina Hotel.
5. Cart Road-Annadale via Kennedy House Chowk.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas Shimla and its surrounding areas are a major tourist attraction and historically the streets of Shimla including the famous 'Mall Road' have been developed on the assumption that they will be used primarily for pedestrian movement. In the recent past, the exponential growth of vehicles official and private, both of residents and tourists has congested the streets and made the pedestrian movement difficult and dangerous particularly on the Mall Road which is used by a large number of pedestrians tourists and school children. Keeping this in view, the State Government had framed a policy dated 8/5/1991. Subsequently, the State Government, in light of the proceedings in CWP No. 505/2000 titled "Citizen Rights Protection Forum & Ors V/S State of H.P. and Ors" reformulated the policy for rationalizing the system for regulation of vehicular traffic in Shimla town. Accordingly, the policy dated 20/12/2003 was issued in which a new permit fee structure was introduced, alongwith other parameters which were required to be kept in view while scrutinizing the applications for the grant of the permits and also prescribing therein the conditions for observance by the permit holders.

In the year 2005, CWP No. 739/2005 and PIL No. 9/2005 titled "Ankush Dass Sood V/S State of H.P. & ors" and "Kishan Singh Verma V/S State of H.P. & ors" respectively were filed in the Hon'ble High Court, seeking therein directions, inter alia, in connection with the issuance of permits for sealed/ restricted roads in Shimla Town by different agencies and other allied matters such as parking of vehicles on different roads/ specific places, over speeding of vehicles on the said roads and un-authorized plying etc. The State Government in pursuance to orders dated 28/9/2005 in CWP No. 739/2005 produced the copy of a draft notification to be issued under section 115 of the Motor Vehicles Act, 1988 before the Hon'ble High Court vide affidavit dated 10/11/2005 and 14.12.2005, specifically averring therein that the approval of Council of Ministers was required to be taken prior to its issuance. The matter was discussed by the Council of Ministers in its meeting dated 21/2/2006 and 14/3/2006 and it was decided that instead of issuing a Notification a legislation be brought on this matter incorporating therein the provisions which were earlier proposed in the draft notification.

The legislation seeks to provide for the definition of sealed and restricted roads and the terms of the grant of passes on payment of fees for plying vehicles on such roads on prescribed conditions. A fund called "the Shimla Road Users and Pedestrians Amenities Fund" is also proposed, in order to improve road safety for pedestrians and vehicles.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH),
Chief Minister.

Shimla:
The 2007.

FINANCIAL MEMORANDUM

Provisions of this Bill shall be enforced through existing Government machinery. As such, there shall be no additional expenditure out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 21 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

**THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRINS (PUBLIC SAFETY AND
CONVENIENCE) BILL, 2007**

A

BILL

to restore the sanctity of the Shimla Mall Road by preventing its use as an thoroughfare and to provide for regulation of vehicular traffic in the interest of public safety and convenience on the sealed and restricted roads of Shimla town to prevent annoyance and injury to pedestrians and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

(VIRBHADRA SINGH),
Chief Minister.

J. N. BAROWALIA,
Principal Secretary (law).

Shimla:

The, 2007.